

नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद की वित्त उप समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक की तिथि : 15-06-2017

स्थान : सभाकक्ष
कृषि निदेशालय
कृषि भवन,
लखनऊ।

समय : पूर्वान्ह 11.00 बजे।

उपस्थित :

- 1- प्रो० अख्तर हसीब, कुलपति - अध्यक्ष
- 2- श्री शिवराम त्रिपाठी, संयुक्त सचिव, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग, उ०प्र०शासन - सदस्य
- 3- श्री योगेन्द्र दत्त त्रिपाठी, संयुक्त सचिव वित्त विभाग, उ०प्र०शासन - सदस्य
- 4- श्री राकेश कुमार त्रिपाठी, वित्त नियंत्रक - सचिव

बैठक के प्रारम्भ में माननीय कुलपति /अध्यक्ष वित्त उपसमिति द्वारा बैठक में प्रथम बार भाग लेने वाले माननीय सदस्य श्री योगेन्द्र दत्त त्रिपाठी, संयुक्त सचिव वित्त विभाग एवं श्री राकेश कुमार त्रिपाठी, वित्त नियंत्रक का स्वागत किया गया, तथा माननीय सदस्यों से परिचय कराया गया, तदोपरान्त बैठक में निम्नवत् प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :-

प्रस्ताव सं० 1 वित्त उप समिति की गत बैठकों के कार्यवृत्त की पुष्टि।

वित्त उपसमिति की गत बैठक दिनांक 27-05-2016 एवं 16-09-2016 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

प्रस्ताव सं० 2 वित्त उप समिति की गत बैठकों में लिये गये निर्णय पर कृत कार्यवाही की सूचना।

वित्त उपसमिति की गत बैठक दिनांक 27-05-2016 एवं 16-09-2016 में लिये गये निर्णय पर की गयी कार्यवाही की सूचना से माननीय सदस्य अवगत हुये एवं सहमति व्यक्त की गयी।

प्रस्ताव सं० 3 नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज फैजाबाद के वित्तीय वर्ष 2016-17 पुनरीक्षित एवं वर्ष 2017-18 अनुमानित आय व्यय पर विचार एवं निर्णय।

वित्त उपसमिति द्वारा विश्वविद्यालय के वित्तीय वर्ष 2016-17 पुनरीक्षित एवं वर्ष 2017-18 अनुमानित आय व्ययक पर सम्यक विचार विमर्श किया गया। आय व्ययक पर सन्धक विचारोंपरान्त वित्त उप समिति द्वारा दिये गये सुझावानुसार परिशिष्ट -क के अनुसार आय व्ययक की संस्तुति सर्वसम्मति से प्रदान की गयी। वित्त उप समिति द्वारा यह सुझाव दिया गया कि विश्वविद्यालय के विज्ञापन के प्रकाशन हेतु विश्वविद्यालय के निदेशक प्रशासन एवं परिवीक्षण सूचना निदेशक उ०प्र० से विश्वविद्यालय के विज्ञापन को शासकीय दर से प्रकाशित कराने हेतु कार्यवाही अपने स्तर से सम्पादित करे। जब तक सूचना विभाग द्वारा शासकीय दर पर अनुमति नहीं दी जाती है तब तक पूर्व व्यवस्था के अनुसार विज्ञापन किटे जायें।

प्रस्ताव सं० 4 विश्वविद्यालय में तदर्थ नियुक्त कर्मचारियों को दिनांक 26-02-2003 के बाद अथवा विनियमितीकरण की तिथि जो भी बाद में घटित हो, से सेवानिवृत्ति लाभ अनुमन्य कराये जाने पर विचार एवं निर्णय ।

वित्त उपसमिति द्वारा विश्वविद्यालय में तदर्थ निरुक्त कर्मचारियों को उनके विनियमितीकरण की तिथि से सेवानिवृत्तिक लाभ दिये जाने संबंधी आदेश को विश्वविद्यालय में अंगीकार किये जाने की सर्वसम्मति से संस्तुति प्रदान की गयी । यदि किसी कर्म द्वारा किसी न्यायालय में वाद दायर किया गया है या कुलाधिपति महोदय या शासन में प्रकरण लम्बित है, तो उसका सेवानिवृत्तिक देयों का भुगतान निर्णय आने के उपरान्त ही किये जाने की संस्तुति की गयी ।

प्रस्ताव सं० 5 वेतन समिति उ०प्र० (2016) के प्रथम प्रतिवेदन भाग -3 में की गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार सचिव, वित्त वेतन आयोग अनुभाग-2, उ० प्र० शासन, लखनऊ द्वारा जारी शासनादेश सं०-66/2016 /वे.आ.-2- 1443 / दस-04(एम)/2016 दिनांक 20 दिसम्बर 2016 इस विश्वविद्यालय के शिक्षणत्तर कार्मिकों के वेतन पुनरीक्षण हेतु लागू किये जाने पर विचार एवं निर्णय ।

वित्त उपसमिति द्वारा वित्त वेतन आयोग, अनुभाग-2 उ० प्र० शासन, लखनऊ द्वारा जारी शासनादेश सं०-66/2016/वे.आ.-2-1443/दस-04(एम)/2016 दिनांक 20 दिसम्बर 2016 को विश्वविद्यालय में अंगीकार किये जाने की सर्वसम्मति से संस्तुति प्रदान की गयी । यदि किसी कर्म द्वारा किसी न्यायालय में वाद दायर किया गया है या कुलाधिपति महोदय या शासन में प्रकरण लम्बित है तो उन कार्मिकों के वेतन का पुनरीक्षण निर्णय आने के उपरान्त ही किये जाने की संस्तुति की गयी ।

प्रस्ताव सं० 6 मान० उच्च न्यायालय, खण्डपीठ लखनऊ में योजित याचिका संख्या 15332(एस.एस.) /2016 विजय कुमार सिंह व अन्य -1 बनाम राज्य सरकार उ०प्र० व अन्य-4 में पारित आदेश दिनांक 06-07-2016 एवं संशोधित आदेश दिनांक 15-07-2016 तथा विशेष सचिव, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र / शासनादेश सं० 473/ 67- कृ.शि.अ.- 16-30 (57) /16 दिनांक 05 अक्टूबर 2016 में दिये गये निर्देशानुसार अवर अभियन्ता संवर्ग के कर्मचारियों से संबंधित पदों की वेतन विसंगति के निराकरण हेतु उच्चिकृत वेतन बैंड-2 रू० 9300-34800 ग्रेड पे रू० 4200/- प्रदान किये जाने पर विचार एवं निर्णय ।

वित्त उपसमिति द्वारा विशेष सचिव, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग, उ०प्र० शासन, वित्त वेतन आयोग अनुभाग-2 उ० प्र० शासन, लखनऊ के पत्र/शासनादेश सं० 473/67-कृ.शि.अ.- 16-30 (57) /16 दिनांक 05 अक्टूबर 2016 को विश्वविद्यालय में अंगीकार किये जाने की सर्वसम्मति से संस्तुति प्रदान की गयी ।

प्रस्ताव सं० 7 रिट याचिका संख्या 1343(एस.बी०)/2007 व रिट याचिका संख्या 1117 (एस. बी०)/2007 में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद, खण्डपीठ लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 11-09-2012 एवं प्रमुख सचिव, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग, के पत्र/शासनादेश सं० 222 / 67-कृ.शि.अ.-16-30(45)/07 दिनांक 19 अप्रैल, 2016 के अनुपालन में प्रबन्ध परिषद की बैठक संख्या 172:3 लिये गये निर्णय पर पुनर्विचार ।

वित्त उपसमिति द्वारा सर्वसम्मति से प्रबन्ध परिषद की बैठक संख्या 172:3 दिनांक 27-05-2016 में लिये गये निर्णय के अनुसार विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से प्रबन्ध परिषद की बैठक दिनांक 27-05-2016 से ही अनुमन्य करने की संस्तुति प्रदान की गयी ।

प्रस्ताव सं० 8 मान० उच्च न्यायालय, खण्डपीठ लखनऊ में योजित याचिका संख्या 5152(एस.एस.)/ 2016 दिनेश प्रताप सिंह व अन्य -33 बनाम राज्य सरकार उ० प्र० व अन्य-3 के आधार पर योजित अवमानना वाद सं० 2437(सी)/ 2016 में पारित आदेश दिनांक 22-12-2016 एवं सचिव, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र/शासनादेश सं० 1568/67-कृ.शि.अ.- 16-200(27)/12 दिनांक 15 सितम्बर 2016 में दिये गये निर्देशानुसार लिपिकीय संवर्ग में कार्यरत कर्मियों से संबंधित पदों की वेतन विसंगति के निराकरण हेतु कनिष्ठ लिपिक /अन्य समकक्ष 91 पद वेतन बैंड रू० 5200-20200 ग्रेड पे रू० 1900/-, वरिष्ठ लिपिक 28 पद वेतन बैंड रू० 5200-20200 ग्रेड पे रू० 2400/- तथा कार्यालय अधीक्षक 03 पद के पुनर्गठन कर उच्च ग्रेड वेतन प्रदान किये जाने पर विचार एवं निर्णय ।

वित्त उपसमिति द्वारा सचिव, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग, उ० प्र० शासन वित्त वेतन आयोग अनुभाग-2 उ० प्र० शासन, लखनऊ के पत्र, शासनादेश सं० 1568/67-कृ.शि.अ.- 16-200 (27)/12 दिनांक 15 सितम्बर 2016 को विश्वविद्यालय में अंगीकार किये जाने की सर्वसम्मति से संस्तुति प्रदान की गयी ।

प्रस्ताव सं० 9 मान० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ में योजित याचिका संख्या 1728(एस.बी०)/ 1999, याचिका संख्या 1726(एस.बी०)/ 1999 एवं याचिका संख्या 88(एस.बी०)/ 2000 के आधार पर योजित अवमानना वाद सं० 1294(सी)/2016 तथा 1295(सी)/2016 में पारित आदेश दिनांक 03-11-2016 एवं विशेष सचिव, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र/शासनादेश सं० 425/67-कृ.शि.अ. - 16-30(45)/07 दिनांक 07 अक्टूबर 2016 में दिये गये निर्देशानुसार याचीगण को वेतनमान रू० 2200-4000 (पुनरीक्षित वेतन बैंड रू० 15600 -39100 ए०जी०पी० रू० 6000/-) प्रदान किये जाने पर विचार एवं निर्णय ।

मान० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ में योजित याचिकाओं के दृष्टिगत उक्त याचिकाओं से आच्छादित 7 याचीगणों के पदों के वेतनमान की विसंगति के निराकरण को अपने स्तर से अनुपालन कराये जाने का आदेश दिया । तदुपरान्त, विशेष सचिव कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग के पत्र/शासनादेश 425/67-कृ.शि.अ. - 16-30(45)/07 दिनांक 07 अक्टूबर 2016 में नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज फैजाबाद को दिशा-निर्देश दिया गया, तदुपरान्त माननीय उच्च न्यायालय के आदेश एवं उ० प्र० शासन के दिशा-निर्देश के अनुपालन करने हेतु विश्वविद्यालय ने 7 कर्मियों को तदानुसार आदेश सं० एन०डी०यू०ए०टी०-16/वि०प्र०/2016/2120 दिनांक 09 दिसम्बर 2016 निर्गत कर दिया गया तथा यह दिशा-निर्देश दिया गया कि उक्त आदेश प्रबन्ध परिषद के निर्णय के अधीन होगा ।

५

दिनांक 15 जून, 2017 की वित्त उपसमिति की बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि उक्त याचिगणों के देय लाभ का अनुमोदन किया जाता है और इन याचिगणों का देय लाभ पुनःयोजित आगामी प्रबन्ध परिषद की बैठक दिनांक 20 जून, 2017 को बुलायी गयी जिसमें इसकी संस्तुति प्राप्त की जायेगी।

प्रस्ताव सं० 10 कृषि निदेशालय उत्तर प्रदेश (राष्ट्रीय कृषि विकास योजना प्रकोष्ठ) कृषि भवन लखनऊ के शासनादेश सं० 1198/12-3-2016-100(5)/2011 दिनांक 22-9-20.16 द्वारा वित्त पोषित परियोजना को इस विश्वविद्यालय में क्रियान्वित किये जाने पर विचार एवं निर्णय।

वित्त उपसमिति द्वारा कृषि निदेशालय उत्तर प्रदेश, (राष्ट्रीय कृषि विकास योजना प्रकोष्ठ) कृषि भवन लखनऊ द्वारा वित्त पोषित परियोजना को इस विश्वविद्यालय में संचालित किये जाने की सर्वसम्मति से संस्तुति प्रदान की गयी।

प्रस्ताव सं० 11 वेतन समिति 2008 के ग्यारहवें प्रतिवेदन के अनुक्रम में इस विश्वविद्यालय में कार्यरत लेखा संवर्ग के कर्मचारियों के पदों की वेतन विसंगति के निराकरण / पुनर्गठन के संबंध में कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ द्वारा निर्गत शासनादेश सं० 38/2016/449/67-कृ.शि.अ.-16-1500 (45) /14 दिनांक 30 जून, 2016 को विश्वविद्यालय में लागू किये जाने के संबंध में विचार एवं निर्णय।

वित्त उपसमिति द्वारा विशेष सचिव, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग, उ०प्र० शासन वित्त वेतन आयोग अनुभाग-2 उ० प्र० शासन, लखनऊ के शासनादेश सं० 38/2016/449/67-कृ.शि.अ.-16-1500 (45) /14 दिनांक 30 जून, 2016 को विश्वविद्यालय में अंगीकार किये जाने की सर्वसम्मति से संस्तुति प्रदान की गयी।

प्रस्ताव सं० 12 इस विश्वविद्यालय के आशुलिपिक संवर्ग से सम्बन्धित पदों की वेतन विसंगति का निराकरण कर उच्चिकृत वेतन निर्धारण एवं पुनर्गठन हेतु जारी कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन, के शासनादेश सं० 166/67-कृ.शि.अ.-17-500 (6) /11 दिनांक 28 मार्च, 2017 को लागू करने पर विचार एवं निर्णय।

वित्त उपसमिति द्वारा संयुक्त सचिव, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग उ०प्र० शासन वित्त वेतन आयोग अनुभाग-2 उ० प्र० शासन, लखनऊ के पत्र/ शासनादेश सं० 166/67-कृ.शि.अ.-17-500 (6) /11 दिनांक 28 मार्च, 2017 को विश्वविद्यालय में अंगीकार किये जाने की सर्वसम्मति से संस्तुति प्रदान की गयी।

प्रस्ताव सं० 13 निदेशालय निर्माण एवं संयंत्र में विद्युत सम्बन्धी कार्यों की देख-रेख एवं अनुरक्षण हेतु स्वीकृत रिक्त पदों के सापेक्ष नियत मानदेय पर कार्मिकों को लगाये जाने पर विचार एवं निर्णय।

वित्त उपसमिति द्वारा प्रकरण पर गहन विचार विमर्श किया गया। सम्यक विचारोपरान्त वित्त उपसमिति द्वारा सर्वसम्मति से यह सुझाव दिया गया कि विश्वविद्यालय में रिक्त पदों को भरे जाने की शासन से अनुमति प्राप्त की जाय। विश्वविद्यालय के आवश्यक कार्य प्रभावित न हो इस दृष्टिकोण से रिक्त पदों को भरे जाने तक सेवानिवृत्त दक्ष एवं स्वस्थ कार्मिकों से प्रार्थनापत्र प्राप्त कर कुलपति द्वारा एक कमेटी का गठन करके

१

सेवानिवृत्त कार्मिकों को पुर्ननियोजन हेतु नियोक्ता प्राधिकारी की अनुमति से रखे जाने की संस्तुति प्रदान की गयी । वेतन का निर्धारण शासनादेश सं० स-सा०-३-302/दस-2013-308/97 टी०सी० दिनांक 22-4-2013 द्वारा किये जाने की भी संस्तुति की गयी ।

प्रस्ताव सं० 14 कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ द्वारा जारी पत्र / शासनादेश सं० 1670/ 67- कृ.शि.अ.-16-400 (25) /07 दिनांक 07 नवम्बर 2016 को इस विश्वविद्यालय के वाहन चालकों हेतु लागू किये जाने पर विचार एवं निर्णय ।

वित्त उपसमिति द्वारा वाहन चालकों को पूर्व में दिये गये लाभ को निरस्त करते हुए संयुक्त सचिव, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग उ०प्र० शासन वित्त वेतन आयोग अनुभाग-2, उ० प्र० शासन, लखनऊ के पत्र/ शासनादेश सं० 1670/ 67- कृ.शि.अ.-16-400 (25) /07 दिनांक 07 नवम्बर 2016 को विश्वविद्यालय में अंगीकार किये जाने की सर्वसम्मति से संस्तुति प्रदान की गयी ।

प्रस्ताव सं० 15 निदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद-अटारी, जी०टी०रोड, रावतपुर कानपुर के पत्र सं० ATTARI/2015 /misc दिनांक 31-7-2015 संयुक्त सचिव, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग, उ०प्र० शासन लखनऊ के पत्र सं० 870 / 67- कृ.शि.अ.-17-1500(3)/16 टी०सी० -1 दिनांक 02-05-2017 एवं कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन जी अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक दिनांक 21-04-2017 के कार्यवृत्ति के बिन्दु-6 के अनुसार कृषि विज्ञान केन्द्रों के कार्यक्रम समन्वयकों / हेड को वित्तीय अधिकार दिये जाने पर विचार एवं निर्णय ।

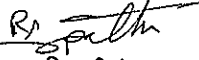
वित्त उपसमिति द्वारा निदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कानपुर के पत्र सं० ATTARI/2015 /misc दिनांक 31-7-2015 के दिशा निर्देश के दृष्टिगत वित्तीय नियमों के अनुसार प्रशासन द्वारा लिये गये निर्णय जो कुलसचिव के पत्रांक 07/स्था/का०अधी०/प्रसार /367 दिनांक 22-5-2017 द्वारा वित्तीय अधिकारों को कृषि विज्ञान केन्द्रों के कार्यक्रम समन्वयकों को दिये जाने हेतु जारी किया गया है, की सर्वसम्मति से संस्तुति प्रदान की गयी (प्रति संलग्न) ।


प्रस्ताव सं० 16 कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्या 2344/ 67- कृ.शि.अ.-16-1500 (159) /07 दिनांक 17 मार्च 2017 में संदर्भित अधिसूचना संख्या 12/2016/524/36-03-2016-01(अधि०) / 2005 दिनांक 15 जून 2016 द्वारा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के पारिश्रमिक में की गयी वृद्धिको विश्वविद्यालय में अंगीकार किये जाने हेतु विचार एवं निर्णय

वित्त उपसमिति द्वारा प्रबन्ध परिषद की 173वीं बैठक के मद संख्या 173:5 के निर्णय को निरस्त करते हुए संयुक्त सचिव, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग उ०प्र० शासन वित्त वेतन आयोग अनुभाग-2 उ० प्र० शासन, लखनऊ के पत्र/ सं० 2344/ 67- कृ.शि.अ.- 16-1500 (159) /07 दिनांक 17 मार्च 2017 में संदर्भित श्रम अनुभाग के अधिसूचना संख्या 12/2016/524/36-03- 2016-01(अधि०) / 2005 दिनांक 15 जून 2016 को विश्वविद्यालय में अंगीकार किये जाने की सर्वसम्मति से संस्तुति प्रदान की गयी तथा

यह निर्णय लिया गया कि भविष्य में उक्त श्रेणी के दैनिक भोगी कर्मचारियों का भुगतान श्रम अनुभाग द्वारा अधिसूचित दरों पर ही सुनिश्चित किया जाय ।

बैठक की कार्यवाही अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ समाप्त हुयी ।

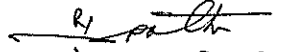

(राकेश कुमार त्रिपाठी)
वित्त नियंत्रक/सचिव
वित्त उप समिति


(अख्तर हसीब)
कुलपति/ अध्यक्ष
वित्त उप समिति

15-06-17

नरेन्द्र देव कृषि एवं औद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद ।

पत्रांक एन0डी0यू0ए0टी0/8/वि0उ0स0/लेखा/2017/ 347 दिनांक 16-06-2017
प्रतिलिपि - प्रबन्ध परिषद के मानन्य सदस्यों के अवलोकनार्थ प्रेषित ।


(राकेश कुमार त्रिपाठी)
वित्त नियंत्रक/ सचिव
वित्त उप समिति

परिशिष्ट-क

नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज ,फैजाबाद
आय-व्ययक पुनरीक्षित व्यय वर्ष 2016-17 एवं अनुमान वर्ष 2017-18

(धनराशि हजार रू० में)

क्रमांक	मुख्य लेखाशीर्षक	पुनरीक्षित व्यय वर्ष 2016-17	प्रस्तावित अनुमान वर्ष 2017-18
1	2	3	4
1	राज्य सरकार आयोजनेत्तर योजनाएं		
क	कृषि विश्वविद्यालय	463645	●641392
ख	पशुचिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय	86681	137581
ग	महामाया कृषि अभियंत्रण एवं तकनीकी महाविद्यालय अम्बेडकरनगर,	13707	19809
घ	प्रसार योजनाओं का सुदृढीकरण(कृषि ज्ञान केन्द्रों हेतु)	182	200
छ	आडिट फीस	10000	32023
ज	नये प्रवेशकों पर नयी परिभाषित अंशदान पेंशन योजना	0	32000
	योग (राज्य सरकार आयोजनेत्तर)	574215	863005
2	राज्य सरकार आयोजनागत योजनाएं		
क	भारतीय कृषि अनु० परि० के सहयोग से संचालित परियोजनाओं हेतु 75:25प्रतिशत परियोजनाओं हेतु 25 प्रतिशत राज्यांश	31125	65458
ख	विश्वविद्यालय में चल रहे विभिन्न निर्माण कार्य	229667	266814
ग	रावे पर व्यय(25 प्रतिशत)	0	1023
घ	पशु चिकित्सा एवं पशुपालन मह विद्यालय में वी०वी०एस०सी०एण्ड ए०एच० पाठ्यक्रम के अन्तिम वर्ष के छात्रों हेतु इन्टर्नशिप कार्यक्रम हेतु राज्यांश	0	253
च	कृषि महाविद्यालय आजमगढ की स्थापना हेतु	1099	30000

26

	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	3639	1
	योग (राज्य सरकार आयोजनागत)	265530	363546
3	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली द्वारा वित्त पोषित योजनाएं		
क	शत प्रतिशत वित्त पोषित कृषि विज्ञान केन्द्रों हेतु	158942	225900
ख	शत प्रतिशत वित्त पोषित शोध योजनाओं हेतु	3244	18238
ग	केन्द्रीय सहायता एन0टी0एस0	0	4000
घ	रावे पर व्यय (75 प्रतिशत)	0	3067
च	पुस्तकालय का सुदृढीकरण	0	10000
छ	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली द्वारा 75:25 प्रतिशत वित्त पोषित योजनाओं की 75 प्रतिशत धनराशि	93304	196373
ज	शिक्षकों के यू0जी0सी0एरियर के भुगतान हेतु	38	2000
	योग	255528	459578
4	अन्य संस्थाओं द्वारा वित्त पोषित योजनाएँ	12117	1337
	योग	12117	1337
5	चकीय निधि	38349	69775
	योग	38349	69775
	सम्पूर्ण योग (1 से 5 तक)	1145739	1757241

- यात्रा व्यय मद में रू0 1000 हजार , स्थानान्तरण यात्रा व्यय में रू0 50 हजार , औषधि तथा रसायन मद में रू0 175 हजार , अन्य व्यय मद में रू0 600 हजार तथा कम्प्यूटर अनुरक्षण / तत्संबंधी स्टेशनरी का कय मद में रू0100 हजार की सीमा तक व्यय करने की संस्तुति की गयी ।

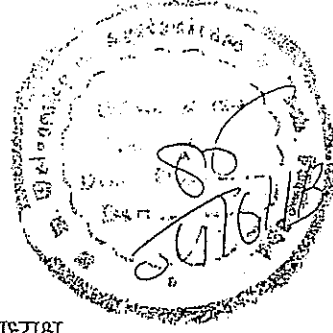
(Handwritten signature)

प्रेषक

आनन्द मिश्र,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- 1-समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
- 2-समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।



वित्त (सामान्य) अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक: 22 अप्रैल, 2013

विषय:- पुनर्योजित सरकारी सेवकों के वेतन निर्धारण के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-सा-3-1443/दस-930/83 दिनांक 15 दिसम्बर, 1983, शासनादेश संख्या-सा-3-2551/दस-946/87, दिनांक 23 दिसम्बर, 1987, शासनादेश संख्या-सा-3-2211/दस-930-83, दिनांक 25 नवम्बर, 1988, शासनादेश संख्या-सा-3-1527/दस-930/83, दिनांक 11 जुलाई, 1989, शासनादेश संख्या-सा-3-1329/दस-97/930/83, दिनांक 27 सितम्बर, 1997, शासनादेश संख्या-सा-3-126/दस-98-902/98, दिनांक 16 मार्च, 1998 तथा शासनादेश संख्या-सा-3-957/दस-1998-902/98, दिनांक 18 जुलाई, 1998 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों के लागू होने के अनन्तर, राज्य सरकार द्वारा पुनर्योजित सरकारी सेवकों के वेतन निर्धारण के सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त निम्नानुसार कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया है :-

(1)- दिनांक 01 जनवरी, 2006 के उपरान्त सेवानिवृत्त एवं पुनर्योजित सरकारी सेवकों को पुनर्योजित पद पर वेतन निर्धारण उनके द्वारा आहरित अंतिम मूल वेतन (वेतन बैंड में बैंड वेतन एवं ग्रेड वेतन के योग) में से शुद्ध पेंशन (राशिकरण के पूर्व) को घटाते हुये किया जायेगा।

(2)- दिनांक 01 जनवरी, 2006 के पूर्व सेवानिवृत्त तथा दिनांक 01-01-2006 के उपरान्त पुनर्योजित सरकारी सेवकों द्वारा पुनर्योजित पद पर उनके द्वारा सेवानिवृत्ति के ठीक पूर्व आहरित अंतिम मूल वेतन काल्पनिक रूप से पुनरीक्षित वेतन संरचना में इस प्रकार निर्धारित किया जायेगा जैसे वह पुनरीक्षित वेतन संरचना में सेवानिवृत्त हुये हों। पुनर्योजित पर उनका वेतन, उपर्युक्तानुसार निर्धारित काल्पनिक पुनरीक्षित वेतन (ग्रेड-में सहित) में से पुनरीक्षित पेंशन (राशिकरण के पूर्व) को घटाते हुए किया जायेगा।

L. Katiyar
1

2013
17
Charan

- (3)- ऐसे राजकीय सेवक जो दिनांक 01-01-2006 के पूर्व सेवानिवृत्त हुए तथा उक्त तिथि को पुनर्योजन में थे, के अपुनरीक्षण भुगतान में आहरित अंतिम मूल वेतन तथा पेंशन का पुनरीक्षण दिनांक 01-01-2006 से उपर्युक्तानुसार करते हुये, पुनर्योजित पद पर उनका वेतन पुनः निर्धारित किया जायेगा।
- (4)- पुनर्योजित पद पर उपर्युक्तानुसार निर्धारित वेतन एवं पेंशन का योग, पुनर्योजित सरकारी सेवक का पुनरीक्षित वेतन संरचना में अन्तिम मूल वेतन (वेतन बैण्ड में बैण्ड वेतन एवं ग्रेड वेतन का योग) (वास्तविक अथवा काल्पनिक, जैसी भी स्थिति हो) अथवा पुनर्योजित पद के वेतन बैण्ड में अधिकतम वेतन तथा ग्रेड वेतन के योग, दोनों में जो कम हो, से अधिक नहीं होगा।
- (5)- वेतन संशोधन संबंधी आदेश संबंधित प्रशासकीय विभाग द्वारा वित्त विभाग की सहमति से जारी किये जायेंगे। इस संशोधन के फलस्वरूप अवशेषों का भुगतान संबंधित कोषागार/संस्था जहाँ से पुनर्योजित सरकारी सेवक वेतन आहरित कर रहा है, द्वारा किया जायेगा।

2- इस आदेश में उल्लिखित पूर्व शासनादेशों की अन्य शर्तें यथावत् रहेंगी। यह आदेश दिनांक 01-01-2006 से प्रभावी होंगे।

भवदीय,

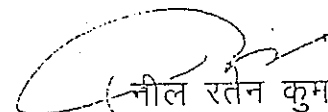
आनन्द मिश्र
प्रमुख सचिव, वित्त।

संख्या-सा-3-302(1)/दस-2013-308/97टी0सी0, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम / द्वितीय, उ0प्र0, इलहाबाद।
- 2- समस्त अनुभाग, उत्तर प्रदेश सचिवालय।
- 3- निदेशक, पेंशन निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
- 4- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0, लखनऊ।
- 5- समस्त मुख्य/ वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
- 6- विधान सभा / विधान परिषद, सचिवालय, उ0प्र0।

आज्ञा से,


(नील रतन कुमार)
विशेष सचिव।